



भारत का यज्ञपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, शनिवार, दर्दि 28, 1977 उपर्युक्त 7, 1899

No. 222] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28 1977 JYASHTHA 7 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह उल्लंग गंभीरन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSIRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 28th May 1977

S.O. 372(E)—Whereas Messrs Alexandra Jute Mills Limited, Calcutta, owning an industrial undertaking is being wound up by the Calcutta High Court and the business of this company is not being continued,

And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary in the interests of the general public and, in particular, in the interests of production of jute articles, to investigate into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking;

And whereas on application made by the Central Government to the Calcutta High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Calcutta High Court has granted the permission;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (75 of 1951) the Central Government hereby appoints Shri K. K. Chitterjee, Industrial Adviser in the Office of the Jute Commissioner, Calcutta, for the purpose of making investigation into the possibility of re-starting the aforesaid industrial undertaking

[No F 3/8/77-CUC]
D. K SAXENA, Jt. Secy.

(2005)

उद्योग मंत्रालय

(श्रीद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मई, 1977

का०पा० 372(प्र)—कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स अंकजांड्रा जृट मिल्स विमिटेड, कलकत्ता, जो कि एक श्रीद्योगिक उपक्रम की स्वामी है, परिसमाप्ति की जा रही है, और इस कम्पनी का कारोबार जारी नहीं रखा जा रहा है;

श्रीर बैन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जनसाधारण के हित में, तथा विरोष स्प से जृट की बस्तुओं के उत्पादन के हित में यह आवश्यक है कि उपरोक्त श्रीद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की सम्भावना की जाए;

श्रीर बैन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को किये गये आदेश पर, जिसने ऐसी सम्भावना की जाच करने की अनुज्ञा देने की प्रार्थना की गई थी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अनुज्ञा प्रदान कर दी है;

प्रत; श्रीद्योगिक (विकास श्रीर नियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की द्वारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैन्द्रीय सरकार, उपरोक्त श्रीद्योगिक उपक्रम को पुनः आरम्भ करने की सम्भावना की जाच; प्रयोगन्, निये श्री ५० क० ८० चटर्जी, श्रीद्योगिक परामर्शी, जृट आयुक्त का कायोलिय कलकत्ता, को इस आदेश के द्वारा नियुक्त करती है।

[सं० पा० 3/8/77-ी यू सी]

दिनेश किशोर सक्सेना, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुप्रिय तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977